Silk Board not to increase prices of filature raw silk released by the State Government.

(ii) Government of Jammu and Kashmir have agreed to supply 20,000 lbs. of Kashmir filature silk exclusively to actual users and manufacturing exporters on the recommendation of the Central Silk Board at fixed prices.

(iii) A proposal to import 60,000 kgs. of raw silk during 1967-68 is also under consideration.

Supply of Cotton to Mills

*700. **Shri A. K. Gopalan:**
Shri P. Gopalan:
Shri P. Ramamurti:

Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Textile Commissioner has asked the cotton traders to give details of stocks of cotton held by them;

(b) if so, the result thereof;

(c) whether any case has been brought to the notice of Government of not taking delivery by the mills of the cotton sold to them by the traders; and

(d) if so, the steps Government have taken in this matter?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The response to this request has been very poor.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

*701. **श्री महाराज सिंह भारती :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में अब तक कितनी पूंजी लगाई गई है तथा उससे कितना लाभ हुआ है ;

(ख) क्या निगम के कर्मचारियों ने सरकार से शिकायतें की हैं कि उक्त निगमों में करोड़ों रुपये का गबन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष को दूर करने, कार्य कुशलता को बढ़ाने तथा फालतू कर्मचारियों का अनुमान लगाने के लिये सरकार द्वारा की जा रही जांच का क्या परिणाम निकला है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 31-3-67 तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम में नियोजित पूंजी लगभग 162 करोड़ रुपये है तथा 1965–66 तक प्राप्त किया गया लाभ 2.3 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग). 22-2-1966 को राष्ट्रीय कोयला संस्था कर्मचारी संघ रांची ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें और बातों के साथ-साथ घूसखोरी आदि के विषय भी शामिल थे । इनकी जांच की गई । ये एक मामले को छोड़ कर जिस पर उपयुक्त कार्यवाही की गई या तो अस्पष्ट निकले या निराधार । संघ ने एक और पत्र 19-12-66 को राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रबन्ध संचालक को भेजा । इस पत्र की एक प्रति मंत्रालय को भेजी गई । इस पत्र में भ्रष्टाचार के विषय निर्देशित थे । राष्ट्रीय कोयला विकास निगम इस पर विचार कर रही है । संघ ने एक और पत्र दिनांक 23-5-67 को भेजा । इसकी भी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम जांच कर रही है ।

(घ) सरकार ने इस प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की है ।